भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1827

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

†1827. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम में परिवर्तित करके इनका रुपांतरण करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के पालधर जिले के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस पहल के अंतर्गत चिन्हित गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत किन विशिष्ट अवसंरचना सुधारों को लक्षित किया गया है तथा गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले पात्र गांवों के एकीकृत विकास के लिए सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' शुरू की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत प्रति गांव 20.38 लाख रुपये (36,428 गांवों के लिए 7276 करोड़ रुपये) की राशि निर्धारित की गई थी और राज्यों को क्षेत्रीय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के पास उपलब्ध केंद्रीय एसटीसी (अनुसूचित जनजाति घटक) और राज्य टीएसपी (जनजातीय उप योजना) निधियों के अभिसरण के साथ ग्राम विकास योजना बनाना अपेक्षित था। ग्रामीण विकास योजना (वीडीपी) का उद्देश्य प्रत्येक चयनित गांव में अंत्योदय मिशन के माध्यम से चिन्हित बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क (मोबाइल / इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल और बिजली से संबंधित अंतरों को दूर करना है।

आज तक देश भर में 17,656 वीडीपी अनुमोदित किए गए हैं और अब तक कुल 2357.50 करोड़ रुपये की राशि की निधियाँ जारी की गई हैं। इसमें महाराष्ट्र के 1542 गांवों (पालघर जिले के 95 गांव) के वीडीपी का अनुमोदन शामिल है। मंत्रालय ने इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य को 134.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और एसएनए अनुपालन प्रस्तुत करने पर राज्य को

179.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारी भरकम एसएनए शेष लंबित है।

पीएम जनमन की सफलता से प्राप्त जानकारी के आधार पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) शुरू किया गया है, जिसमें पीएमएएजीवाई के तहत आने वाले गांवों सहित 63000 से अधिक गांव शामिल होंगे। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार महाराष्ट्र में 4975 गांव होंगे।

जिले की संख्या	ब्लॉक की संख्या	गावों की संख्या	कुल जनसंख्या	अजजा जनसंख्या	% अजजा
32	214	4975	6347798	4694682	73.96

राज्य सरकार को इन गांवों को डीए-जेजीयूए के तहत कवर करने की सलाह दी गई है, जो संबंधित मंत्रालयों और राज्य विभागों के प्रमुख उपायों के लिए निधियों के समर्पित अभिसरण और संतृप्ति के साथ पीएमएएएजीवाई का अधिक संरचित संस्करण है। इसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय उपायों के लिए समर्पित निधियां प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पीएमएएजीवाई में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

*****